WRITTEN ANSWER TO QUESTIONS

Cuts in Funds for P.S. Us.

*122. SHRI SUKOMAL SEN : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government have decided to enforce further cuts in the funds for public sector undertakings; and

(b) If so, what are the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI) : (a) and (b) : Fund allocation to public sector enterprises is done on merits of the cases depending upon economic viability of projects and availability of resorces. The total plan and non-plan investments in central Public Enterprises during 1993-94 (RE) was Rs. 29011.04 crores and in 1994-95 (BE) is Rs. 33622.11 crores.

लम्बित केन्द्रीय प्रशासनिक मामले

*124 **श्री राम सिंह राठवा** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1994 की स्थिति के अनुसार कितने केन्द्रीय प्रशासनिक मामले लम्बित हैं ;

(ख) सरकार इनके शीघ्र निपटान हेतु क्या प्रयास कर रही है ; और

(ग) क्या यह सच है कि ऐसे मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा) :

(क) 31 जनवरी, 1994 को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में 39,994 मामले लम्बित थे।

(ख) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के उपाध्यक्षों तथा सदस्यों के चयन के लिए पहले ही कदम उठाए गए है ताकि इन पदों के खाली होने के तत्काल बाद वे पदों का कार्यभार संभाल सके । इसके परिणामस्वरूप 1992 और 1993 के दौरान मामलों को निपटाने में पर्याप्त वृद्धि हुई है । केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में लम्बित मामलों को सरकार आवधिक विवरणियों के द्वारा मोनिटर करती है ।

(ग) असल में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की विभिन्न न्यायपीठों में लम्बित मामलों की संख्या निरन्तर घट रही है । वर्ष 1992 के अन्त में लंबित मामलों की संख्या 41035 थी, जो घट कर 1993 के अन्त में 40028 रह गई और जनवरी, 1994 के अंत में यह और घटकर 39994 रह गई । यह स्थिति इस तथ्य के बावजूद है कि नये मामलों का दर्ज होना बढ़ा है । 1992 में 25,184 नये मामले दर्ज किये गये जबकि 1991 में 21,623 नये मामले दर्ज किये गये थे । 1993 में 27,057 नये मामले दर्ज किये गये । 1994 में केवल जनवरी माह के दौरान 2318 मामले दर्ज किए गये हैं ।

बिहार में प्रस्तावित विकास केन्द्रों की समीक्षा

*128. **श्री ब्रह्मदेव आनन्द पासवान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार-सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत चार स्थानों अर्थात् भागलपुर, हजारीबाग, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के संबंध में परियोजना-प्रतिवेदन प्रस्तुत किये है ;

(ख) क्या बिहार सरकार ने इस प्रयोजनार्थ 352 लाख रुपये की राशि जारी की है;

(ग) क्या उद्योग मंत्रालय ने भी उक्त विकास केन्द्रों की अगस्त, 1993 में समीक्षा की है ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार इसे कार्यान्वित करने का विचार रखती है ; और

(ङ) यदि हां, तो निधियां कब तक जारी कर दी जायेंगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?